

>

Title: Regarding framing schemes/policies to improve education, employment and basic facilities in Bihar.

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके संरक्षण में एक विषय जो निरंतर उठता रहा और पूरा भारत सुनता रहा, उस संबंध में मैं बिहार के माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है। उनका यह बयान पूरे देश की जानकारी में आया है कि बिहार पिछड़ा हुआ है। मैं इस बयान का स्वागत करता हूं और मैं यह भी मानता हूं कि इस देश के प्रधान मंत्री जी भी बिहार के प्रति सचेत हैं और देश की सरकार भी कभी यह नहीं कहती है कि बिहार के विकास को हम छोड़कर चलेंगे। हमारे प्रधान मंत्री जी का यह भी मानना है कि बिहार के विकास के लिए पैसे की जितनी भी जरूरत होगी, हम उपलब्ध कराएंगे।

महोदय, सदन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इस विषय को हम लोगों ने उठाया है, लेकिन जहां निवेश चाहिए, वहां नीति की जरूरत होती है और बिना नीति के निवेश करना संभव नहीं हो पाता है, यह हम सभी जानते हैं। मूलतः सदन के भीतर जब हम आते हैं तो नीति बनाते हैं और फिर भारत सरकार नीति के आलोक में पैसे देती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि आज बिहार को पिछड़े राज्य का दर्जा मिल रहा है, तो हमारी नीति क्या है? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आखिर बिहार में जो लाखों छात्र अपना राज्य छोड़कर बाहर पढ़ने जाते हैं, उन्हें बिहार में पढ़ने हेतु रोकने के लिए हमारी क्या नीति है? करोड़ों की संख्या में मजदूर, गरीब बिहार छोड़कर बाहर काम करने जाते हैं। उनको बिहार में रोकने की नीति क्या है? बिहार में कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है और न ही पिछले 70 सालों में इस देश का ऐसा कोई उद्योगपति है, जो बिहार का हो। इस तरह की एक भी ऐसी संरचना नहीं है। हमारे राज्य में न तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है और न ही ऐसे किसी

अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल की व्यवस्था आज तक बिहार में हो सकी है । आखिर इसका रोडमैप क्या है? आज तक बिहार में एक भी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का निर्माण नहीं हुआ है । बेंगलुरु, कर्नाटक, हैदराबाद, दिल्ली में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बना है । बिहार में नागर विमानन की क्या नीति है?

महोदय, इसी प्रकार से मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज बिहार के सबसे ज्यादा छात्र बाहर के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं । आपके शहर कोटा में जाकर यदि बिहार के छात्र पढ़ते हैं, तो फिर बिहार में क्या शिक्षा नीति है? पूरे देश के बड़े-बड़े बड़े-बड़े शहरों में आईटी सेक्टर्स हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर्स हैं, शहरी विकास है, तो फिर बिहार में उसके लिए क्या नीति है? मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इस संबंध में पूरी नीति स्पष्ट करे, ताकि बिहार के गरीबों, मछुआरों, किसानों आदि की बात को हम आगे बढ़ा सकें और एक अच्छी नीति के साथ निवेश करके बिहार को आगे बढ़ाया जा सके । मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का ध्यान उपरोक्त विषयों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । धन्यवाद ।